

पंचवर्षीय योजना में कृषि बाजार

### (Agricultural Marketing in five year planning)

प्रथम पंचवर्षीय योजना (First Five Year Plans) में कृषि-बाजार की समस्या के विकास पर्याप्त मात्रा में जोर दिया गया था। योजनाकाल में कृषि बाजारों को नियमित बाजारों में बदलने पर जोर था। नियमित बाजारों की संख्या 1950-51 ई० में कुल 265 से बढ़कर 1955-56 ई० में 450 हो गयी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना (Second Five Year Plan) में ग्रामीण साख अर्पण समिति के प्रस्तावों के आधार पर केन्द्र में एक अखिल भारतीय गोदाम निगम (All India Warehousing Corporation) का गठन हुआ। द्वितीय योजना के अंतर्गत नियमित बाजारों की संख्या 1955-56 ई० में 450 से बढ़कर 1960-61 ई० में 725 हो गयी। उपज के वर्गीकरण तथा नमूना बनाने की सुविधाओं के विस्तार पर भी द्वितीय योजनाकाल में पर्याप्त जोर दिया गया। द्वितीय योजनाकाल में 180 प्राथमिकता सहकारी विक्रय समितियों की स्थापना की गयी थी तथा साथ ही, एक National Co-operative Marketing Federation की भी स्थापना की गयी। तृतीय पंचवर्षीय योजना (Third Five Year Plan) के अंत तक 1000 बाजारों को भी इसके अंतर्गत लाया गया था। तृतीय पंचवर्षीय योजना में गोदामों (Ware Houses) के निर्माण पर 23 करोड़ रुपये व्यय का आयोजन था जबकि वास्तविक व्यय इस मद में 24 करोड़ रुपये हुआ।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (Fourth Five Year Plan) में भी कृषि-बाजार व्यवस्था के विकास पर पर्याप्त जोर देने का आयोजन था। मार्च, 1968 तक देश में कुल 853 बाजारों को नियमित बाजारों के अंतर्गत लाया गया था। शेष बाजारों को भी चतुर्थ योजना के अंत तक नियमित बाजार के अंतर्गत लाने का आयोजन था। किन्तु दिसम्बर, 1974 तक कुल 3016 बाजारों को ही नियमित बाजार के अंतर्गत लाया जा सका।

पाँचवीं पंचवर्षीय योजना (Fifth Five Year Plan) में भी कृषि बाजार को सद्बढ़ बनाने पर पर्याप्त जोर दिया गया था। योजनाकाल में इस मद में 344 करोड़ रुपये व्यय की व्यवस्था थी। इसके अतिरिक्त गोदाम तथा संचय गृहों की मद में 104 करोड़ रुपये व्यय की व्यवस्था थी। पाँचवीं योजना के अंत तक सभी बाजारों को नियमित बाजार बनाने का आयोजन था जो पूरा नहीं हो सका। साथ ही योजना के अंत तक, यानी 1974-75 में सहकारी समितियों के माध्यम से 1900 करोड़ रुपये के कृषि-पदार्थों के विक्रय का आयोजन था।

(5)

छठी पंचवर्षीय योजना (Sixth Five Year Plan) में भी कृषि-बाजार व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने का प्रयास और दिशा दिया गया है। छठी योजना में कृषि-बाजार की व्यवस्था पर 96 करोड़ रुपये व्यय का आयोजन था। इसके अतिरिक्त गोदाम तथा संचय-गृहों के निर्माण पर 388 करोड़ रुपये व्यय की व्यवस्था थी। छठी योजना के प्रारम्भ में कुल 4452 नियमित बाजार थे। इनकी संख्या बढ़कर योजना के अंत में 5600 हो गयी। साथ ही, योजनाकाल में 34 लाख टन की क्षमता के और अधिक गोदाम तथा संचय-गृहों का निर्माण पर कुल 150 करोड़ रुपये व्यय का आयोजन था। योजनाकाल में अत्यधिक नये बाजारों को नियमित बाजार के अंतर्गत लाने का भी आयोजन था।

आठवीं पंचवर्षीय योजना (Eighth Five Year Plan) में भी देश के सभी प्रामाण्य बाजारों को नियमित बाजार के अंतर्गत लाने का आयोजन था किन्तु यह कार्य सफल नहीं हो सका तथा 1995-96 तक नियमित बाजारों की संख्या 4200 ही हो पायी।